

भेदभाव मिटाने निकले नियम खुद बने विवाद की वजह, छात्रों का भविष्य फिर बना प्रयोगशाला

UGC के इच्छिती नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

आलोक तिवारी / रायपुर

अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी नीति, जो भ्रम और विवाद को जन्म दे, उसे लागू नहीं किया जा सकता

देश के कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों—आईआईटी, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, बीएचयू और केंद्रीय विश्वविद्यालयों से नियमों के विरोध में आवाजें उठी थीं। कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए और आकस्मिक माहौल प्रभावित हुआ। मामलों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए नियमों को अस्पष्ट, असंतुलित और दुरुपयोग योग्य बताया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी नीति, जो भ्रम और विवाद को जन्म दे, उसे लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट के आदेश के बाद 2012 के पुराने नियमों को अस्थायी रूप से लागू कर दिया गया है।

मानना है कि इन नियमों में भेदभाव को परिभाषा को केवल SC/ST/OBC वर्ग तक सीमित कर देना एकतरफा सोच का परिणाम था। इससे सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य समुदायों के छात्रों को न्याय की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।

इस विषय पर शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी छात्र के साथ भेदभाव, उसकी जाति या वर्ग देखकर नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों और मानसिक उत्पीड़न से होता है। ऐसे में नियमों को सीमित दायरे में बांधना सामाजिक न्याय की

भावना के विपरीत माना जा रहा है। नए नियमों में झूठी शिकायत पर डंड का प्रावधान हटाए जाने को भी गंभीर चूक बताया जा रहा है। इससे विश्वविद्यालय परिसरों में भय और असमंजस का माहौल बन गया था। कई शिक्षकों और छात्रों ने आशंका जताई थी कि यह व्यवस्था व्यक्तिगत द्वेष और दबाव बनाने का माध्यम बन सकती है।

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बार-बार नियमों में बदलाव से छात्रों का भविष्य अस्थिर होता जा रहा है। हर नई सरकार और हर नया



आयोग नई व्यवस्था लागू कर देता है, जिससे शिक्षा नीति एक प्रयोगशाला बनकर रह गई है। इस पुरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे भेदभावपूर्ण नीति बताया है, जबकि सरकार ने इसे सुधार का प्रयास कहा है। लेकिन इस राजनीतिक खींचतान में सबसे अधिक नुकसान छात्रों को उठाना पड़ा है। UGC की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल

अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मॉडल से भी सीख लेने की आवश्यकता

विशेषज्ञों का सुझाव है कि भविष्य में नियम बनाने समय सभी वर्गों को समान संरक्षण, पारदर्शी जांच प्रणाली और जवाबदेही व्यवस्था को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मॉडल से भी सीख लेने की आवश्यकता है। अंततः यह स्पष्ट है कि शिक्षा व्यवस्था किसी भी प्रयोग का माध्यम नहीं हो सकती। छात्र केवल डिग्री नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और न्याय चाहते हैं। नीति वही सफल होगी, जो सभी के लिए समान, स्पष्ट और भरोसेमंद हो।

संवेदनशीलता और संवाद जरूरी

भेदभाव मिटाने की लड़ाई कानून से नहीं, संवेदनशीलता और संवाद से जीती जाती है। UGC को अब केवल आदेश जारी करने वाला संस्थान नहीं, बल्कि भरोसे और संतुलन का प्रतीक बनना होगा।



देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवाल के घेरे में आ गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा लागू किए गए इच्छिती रगुलेशंस-2026 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद शिक्षा जगत में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। अदालत के इस फैसले को न केवल कानूनी हस्तक्षेप माना जा रहा है, बल्कि इसे नीति निर्माण में हुई गंभीर चूक पर सख्त चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है।

UGC द्वारा भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से बनाए गए इन नियमों को लेकर शुरूआत से ही आपत्तियां सामने आने लगी थीं। विशेषज्ञों का

हाईकोर्ट के निर्देश पर सब इम्पेक्टर लाइन अटैच, एसपी ने लिया बड़ा एक्शन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग



जिले के स्मृतिनगर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक गुर्विंदर सिंह संघु को चुपचाक को पद से हटाकर रक्षित केंद्र (लाइन अटैच) भेज दिया गया है। यह कारवाई छत्रीसमूह हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद की गई है, जिसने उनके आचरण की जांच कराने का आदेश पुलिस महानिदेशक (डीओपी) को दिया था। सूत्रों के अनुसार, गुर्विंदर सिंह पर दो व्यवसायियों के साथ मनमानी, अमानवीय व्यवहार और नियमों की अनदेखी कर कारवाई करने के गंभीर आरोप लगे थे। इन्होंने आरोपों के चलते पुलिस अधीक्षक ने यह प्रशासनिक कदम उठाया है।

व्यवसायियों के साथ कथित अमानवीय व्यवहार बना वजह
जनकारी के मुताबिक, व्यवसायी सुजीत साव समेत चार लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि सुजीत साव को महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर चौकी लाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई इतना ही नहीं, जेल भेजने से पहले उसे हथकड़ी पहनकर सार्वजनिक रूप से सड़कों पर घुमाया गया और तब करीब 9 बजे जेल में दखिल कराया गया। इस पूरी कार्रवाई को कोर्ट ने नियमों के विपरीत और मानवाधिकारों का उल्लंघन माना।

हाईकोर्ट की सख्ती, डीजीपी को दिए थे जांच के आदेश
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा था कि एसआर गुर्विंदर सिंह संघु की कार्रवाई अनुचित प्रतीत होती है। कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए थे कि मामले को उपयुक्त स्तर पर जांच कराई जाए और दोष सिद्ध होने पर विधि के अनुसार सुचारुतमक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। कोर्ट के निर्देशों के बाद ही अब यह प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है, जिसे पुलिस विभाग में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

नई डिम्बेवती राजेश वाहू को
गुर्विंदर सिंह संघु की जगह भिलाई भद्री थाना प्रभारी राजेश कुमार साहू को स्मृतिनगर चौकी का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। पुलिस प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि नई व्यवस्था से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और पारदर्शिता मजबूत होगी। इस कार्रवाई के बाद जिले के पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। इसे न्यायालय के आदेशों के पालन और पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जाकारों का कहना है कि यह मामला पुलिसकर्मियों के लिए चेतावनी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अधिकारों का दुरुपयोग बदले नहीं किया जाएगा।

बजट 2026-27: विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का महा-एजेंडा

इन्फ्रा, MSME और ग्रामीण भारत पर बड़ा दांव — मिडिल क्लास को टैक्स राहत की उम्मीद



संदीप सिंह / नईदृष्टि

केंद्रीय बजट 2026-27 को मंत्री सरकार के 'विकसित भारत 2047' विजन का आर्थिक रोडमैप माना जा रहा है। 1 फरवरी को पेश होने वाला यह बजट मुख्य रूप से ढांचागत विकास, रोजगार सृजन, टैटएफ को मजबूती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विस्तार पर केंद्रित रहने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए इन्फ्रा और राजकोषीय घाटे के बीच संतुलन कायम करना है।

मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत की तैयारी

इस बार बजट से मध्यम वर्ग को ऐतिहासिक राहत मिलने की उम्मीद है। संभावित फैसले—नए टैक्स रीजिम में रेट-डिडिक्टेशन। लाघ तब बढ़ाने की संभावना, होम लोन और बीमा पर अतिरिक्त छूट, महिलाओं के लिए विशेष टैक्स डेड्यूक, विशेषज्ञों के अनुसार, इससे करोड़ों परिवारों की डिस्पोजेबल आय में सीधा इजाफा होगा।

युवा शक्ति और रोजगार पर फोकस

बजट 2026 में 'जनरेशन' को केंद्र में रखा जा सकता है। रिस्क डेवलपमेंट मिशन का विस्तार, पहली बार निवेश करने वालों को प्रोत्साहन, स्टार्टअप के लिए नई फंडिंग स्कीम, डिजिटल और ऑनलाइन कार्यालय सरकार का लक्ष्य युवाओं को नौकरी देने के साथ-साथ उद्यमी बनाना है।

टैटएफ और मैनुफैक्चरिंग को नई ताकत

देश की रीढ़ मजबूत करने के लिए टैटएफ सेक्टर के लिए राहत पैकेज संभावित है। कस्टमर ड्यूटी में कटौती, लेकिन अफसरों की और से कोई टोस अध्यायन नहीं मिला। धरने के बाद ही विरिष्ठ अधिकारियों की नींद टूटी और औपचारिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई।

इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेगा विकास का इंजन

देश की विकास रफ्तार को तेज करने के लिए पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी तय मानो जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे, रेलवे में फव्व 4.0' सुरक्षा प्रणाली, मेट्रो और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ग्रामीण सड़क नेटवर्क इन्फ्रा सेक्टर में निवेश से लाखों नए रोजगार पैदा होने की संभावना है।

तैयार होगा भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट

बजट 2026-27 सिर्फ सालाना लेखा-जोखा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। अगर रोजगार, टैटएफ, ग्रामीण विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर संतुलित फोकस होते हैं, तो यह बजट देश को 'विकसित भारत' की दिशा में निर्णायक मोड़ दे सकता है।

बजट का खास ध्यान रहेगा।

आर्थिक रोडमैप यह बजट आर्थिक विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन साधने का प्रयास करेगा। सरकार का लक्ष्य—राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखना, निवेश बढ़ाना, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन को प्राथमिकता है।

भू-माफियाओं के आगे बेबस भिलाई निगम, पार्षद धरने पर

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

दुर्ग जिले में अवेध प्लॉटिंग और शासकीय जमीन पर कब्जे का घंघा खुलेआम फल-फूल रहा है, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। अफसरों की इसी लापरवाही और उदासीन रविये से आहत होकर अब जनताप्रतिनिधियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। गुरुवार को वार्ड क्रमांक 13 कोहका की पार्श्व अंबुज सिन्हा भिलाई नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और आयुक्त कार्यालय के बाहर घंटों धरने पर बैठकर प्रशासन की कार्यशैली को खिलफत विरोध दर्ज करवाया।



अफसरों की चुप्पी ने बढ़ाए भू-माफियाओं के हौसले

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि निगम अधिकारियों की चुप्पी और दिलवाई ने भू-माफियाओं को हौसले बुलंद कर दिए हैं। कार्रवाई के अभाव में कब्जाधारियों को खुली छूट मिल गई है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त दिखाई जाती, तो आज हालात इतने बिगड़ते नहीं।

पार्श्व अंबुज सिन्हा ने बताया कि कोहका वार्ड-13 क्षेत्र में लंबे समय से शासकीय भूमि पर अवेध कब्जा और प्लॉटिंग हो रही है। भू-माफिया मिट्टी डालकर जमीन समतल कर रहे हैं और अनैवध निर्माण खड़ा कर दिया जा रहा है। इस संबंध में कई बार निगम अधिकारियों को लिखित और मौखिक शिकायतें

दी गईं, निरीक्षण भी हुआ, लेकिन हर बार मामला फाहलों में दबकर रह गया।

जनता पूछ रही सवाल

अब क्षेत्रवासियों में यह सवाल गुंज रहा है— क्या निगम अधिकारी भू-माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं? शिखरों के घाट भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों पर कब गिरेगी गाज?

भवन अनुज्ञा शाखा भी सवालियों के घेरे में

अवेध निर्माण रोकने के लिए बनाया गए भवन अनुज्ञा विभाग की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। निगम मुख्यालय और जोन कार्यालय में मौजूद इस विभाग के बाबजूद अवेध निर्माण बेरोकटोक जारी हैं। जाकारों का कहना है कि भवन अनुज्ञा सेवकन की निष्क्रियता या मिलीभगत के बिना इतना भवन अवेध खेल संभव नहीं है।

धरना बना मजबूती

अधिकारियों की अनदेखी से परेशान होकर पार्श्व अंबुज सिन्हा को मजबूरन निगम मुख्यालय में धरने पर बैठना पड़ा। दोपहर से देर शाम तक वे आयुक्त कार्यालय के बाहर उठते रहें, लेकिन अफसरों की ओर से कोई टोस अध्यायन नहीं मिला। धरने के बाद ही विरिष्ठ अधिकारियों की नींद टूटी और औपचारिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई।

देर से जागा प्रशासन

पार्श्व के दबाव और सार्वजनिक आक्रोश के बाद निगम आयुक्त राजीव पाण्डेय ने जोन आयुक्त अजय राजपूत को शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके बाद स्मृतिनगर चौकी में अंबुज भू-माफियाओं के खिलाफ आंदोलन दिया गया। हालांकि, रमायावार लिखे जाने तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी थी।

राज्यपाल रमेन डेका ने किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद



नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने आज यहां लोकभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पतीर्थ पर उनके छायाचित्र पर पुष्पजली अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा है कि महात्मा गांधी ने

खास खबर

भिलाई नगर, पाटन और अहिलारा विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत

नई दृष्टि/दुर्ग

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत भिलाई नगर, पाटन और अहिलारा विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पर विकास कार्यों के लिए कुल 34 लाख 38 हजार 94 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा द्वारा अनुशंसित इन कार्यों के तहत भिलाई नगर विधानसभा में बाई 63 होसना चौक के पास सार्वजनिक टॉन शेड निर्माण एवं कांक्रीटकरण हेतु 4 लाख 99 हजार 698 रूपए, बुद्ध विहार के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु 2 लाख 49 हजार 517 रूपए, सेक्टर 06 की सड़क 60-61 के मध्य सार्वजनिक डीम शेड निर्माण हेतु 5 लाख 99 हजार 684 रूपए तथा सेक्टर 07 सड़क 35 के डीम शेड में फेंसिंग कार्य हेतु 1 लाख 49 हजार 739 रूपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी क्रियान्वयन एजेंसी आयुक्त नगर निगम भिलाई हैं। इसी प्रकार पाटन विधानसभा के अंतर्गत नगर पालिका परिषद कुम्हारी के बाई 16 लोटस सिटी में शेड निर्माण हेतु 4 लाख 99 हजार 456 रूपए की स्वीकृति दी गई है, वहीं अहिलारा विधानसभा के ग्राम पंचायत हवेलीडीह में सी.सी. रोड निर्माण हेतु 2.40 लाख और ग्राम कुटुलाभाटा में सरसती शिशु मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 12 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, सभी कार्यों के संपादन हेतु संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

डॉ. श्रीणिक नाहटा "भारत सेवा रत्न सम्मान" से हुए सम्मानित



दुर्ग। देशभर में सामाजिक सेवा, राष्ट्र हित और मानव कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में गणतंत्र दिवस पर समारोहपूर्वक सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वाई-एस-एच इंडिया द्वारा किया जाता है। यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर निःस्वार्थ सेवाभावियों को विभिन्न प्रकारों से सम्मानित करती है।

गणतंत्र दिवस पर जस्टिस एन-के-जैन, आई पी एस निरंजन जैन, ग्रुप कैप्टन आर-बी. पिपाठी, कैप्टन सुखराम यादव, आईपीएस हेमन्त सिंह, ले. कर्नल शोभनकृष्ण गायकवाड, आर्मी ऑफिसर मुकेशकुमार, सी. के. समसेना, बलवीर सिंह, वरिष्ठ प्रकाश डा. अश्विन बंसल, संस्थान अध्यक्ष कमल चौधरी के आतिथ्य में दुर्ग के दंत चिकित्सक डॉ. श्रीणिक नाहटा को अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न निःस्वार्थ सेवा के लिए "भारत सेवा रत्न सम्मान" से अलंकृत किया गया। उल्लेखनीय है कि डॉ. श्रीणिक समाज के निर्धन जरूरत مند लोगों की निःशुल्क उपचार करने के साथ साथ भारत के अनेकों धर्मरूपों की सेवा में निरंतर समर्पित रहते हैं। इनकी अनेकों संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया गया है, जलंधर पद्धति से बिना निश्चयन किए अल्प समय में दांत निकालने और उपचार करने में महारत हासिल है, मात्र 30सेकंड में दांत निकालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सम्मान प्राप्त होने पर दुर्ग के विभिन्न संस्थाओं, प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा बधाई देते हुए प्रसन्नता व्यक्त किया गया।



नई दृष्टि/भिलाई

शायप फाउंडेशन द्वारा बहुप्रतीक्षित 'थैक्यू' कार्यक्रम

'जीवन दर्पण केवल एक खिलाड़ी की जीवनी नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की प्रेरक गाथा

दृष्टिहीन शतरंज खिलाड़ी व महाविद्यालयीन छात्र भूपेंद्र की संघर्षगाथा पर आधारित पुस्तक 'जीवन दर्पण' का राकेश पाण्डेय ने किया विमोचन

नई दृष्टि/भिलाई

दृष्टिहीन शतरंज खिलाड़ी एवं एम.ए. अंतिम वर्ष (हिंदी) के छात्र भूपेंद्र पटेल की प्रेरणादायी जीवन यात्रा पर आधारित पुस्तक 'जीवन दर्पण' का विमोचन भिलाई में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय एवं बिन्दुज फोडे टेड चेस चैम्पियनशिप के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के अन्तर्भूत पर सम्पन्न हुआ। पुस्तक का विमोचन मुख्य अतिथि राकेश पाण्डेय (अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामीणोद्योग बोर्ड, छत्तीसगढ़ शासन) के करमल्लो से किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता वंशी अग्रवाल (अध्यक्ष, अन्वयन जन कल्याण समिति) ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी कैलाश जैन बरमेचा, अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी वृत्तम फोडे मास्टर सुश्री किरण अग्रवाल तथा राज्य शतरंज संघ के कायकर्मी सदस्य रमेश अग्रवाल की

कुरुद में निगम लगाएंगा सीबीजी प्लांट, विरोध में बैठी महिलाएं, कचरे से गैस बनाने की है योजना

बायो गैस प्लांट को लेकर महिलाओं में आक्रोश, कहां नहीं लगने देंगे प्लांट चाहे हमें अपनी जान ही ब्यू ना देने पड़े

नई दृष्टि/भिलाई

शहर से रोज करीब 300 टन से ज्यादा कचरा निकलता है। नगर निगम भिलाई इन कचरों को परमार्सेट निपटान के लिए सीबीजी प्लांट लगाने की योजना बनाई है। जहां शहर भर के कचरे से बायो गैस बनाया जाएगा।

शासन की योजना के तहत निगम ने कुरुद बस्ती क्षेत्र में प्लांट लगाने की योजना बनाई है। काम भी शुरू कर दिए हैं। निगम ने प्लांट लगाने चूना मार्किंग और पोल लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस प्लांट को लेकर कुरुद और आसपास क्षेत्र के सुंदर विहार कालोनी, घासी दास नगर, कैलाश नगर की महिलाएं एकजुट होकर हड़ताल पर बैठ गई हैं। अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठी महिलाएं जमकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं।

महिलाओं ने कहा कि वे अपने क्षेत्र में सीबीजी बायो गैस प्लांट किसी भी हाल में खुलने नहीं देंगे। सैकड़ उन्हें अपनी जान ही न्याय ना देने पड़े। सैकड़ों की संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ कुरुद प्लांट अंतिम साहू भी हड़ताल पर है। उन्होंने बायो कि 6 माह से वे बाई की महिलाओं के साथ जिन आयुक्त से लेकर निगम आयुक्त, कलेक्टर तक से शिकायत कर चुकी है।



प्रदूषण और बीमारी का खतरा

वाढवसियों का कहना है कि प्लांट लगाने तो पूरे शहर का कचरा उनके बाई में जमा होगा। चारों ओर प्रदूषण और गंगी की बदबू फैलेगी। गंभीर बीमारी का खतरा बना रहेगा। इसलिए ए दे प्लांट का विरोध कर रहे हैं। सिर्फ यहीं नहीं कुरुद में कृष्णा कुज बना है। जहां हर बरें पड़े पड़े लगे है। उसे भी काटने की तैयारी चल रही है।

बावजूद कोई पहल नहीं हुई तो उन्होंने सामान्य सभा में मुद्दा उठाया था और खुलकर विरोध कर प्लांट नहीं लगाने की मांग की थी। सामान्य सभा में समाप्त से लेकर महापौर व सभी पार्षद व अधिकारियों को

प्लांट नहीं लगाने की मांग की। बावजूद जब कोई पहल नहीं हुई तो उन्होंने वैशाली नगर विधायक किशोर सेन से भी मांग किए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि प्लांट नहीं खुलने देंगे। यदि धरना प्रदर्शन करने की

नौबत आएगी तो वे भी उनके साथ बैठेंगे। लेकिन अब तक विधायक नहीं आए हैं। महिलाओं ने कहा कि उन्हें विधायक से पूरी उम्मीद है। यदि वे चाह लेंगे तो प्लांट नहीं

खुलेगा। इस अवसर पर रानी सिंह, लीला, दुलारी देवीगन, उमिल्ली यादव, जायसवाल, आशा, सरोजनी सहित सैकड़ों महिलाएं शामिल रही।

जिले भर के निकायों से लेंगे कचरा

नगर निगम भिलाई, दुर्ग, रिसाली और भिलाई-चरोटा से हर रोज करीब 150 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। सिर्फ भिलाई से रोज 200 टन कचरा निकलता है। इसमें 40 प्रतिशत गीला कचरा होता है। प्लांट को रोज 150 से 200 टन गीला कचरा लगेगा। इसके लिए जिले भर के निकायों से निकले वाले कचरे को प्लांट को दिया जाएगा। जिससे प्लांट में गैस बनाया जाएगा। इससे कचरा प्रोसेसिंग कर खाद बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

'गौवश से ही होगा पंच परिवर्तन' जैसे अहम विषय पर डाला प्रकाश, बताई गौमाता की उपयोगिता और महता



नई दृष्टि/भिलाई

छत्तीसगढ़ की शिक्षाधीनी भिलाई स्थित सेक्टर-7 के कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गौ विज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की संरक्षण एवं संवर्धन समिति रायपुर के द्वारा गौ विज्ञान परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया। समिति के द्वारा प्रवेश परी में तीन श्रेणियों में प्रथम श्रेणी का अंकों का प्रतिभागी को 31 सी रूपए, द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 21 सी रूपए और तृतीय श्रेणी पर आने वाले प्रतिभागी को 11 सी रूपए प्रदान किया जाएगा। जबकि राज्य स्तर पर प्रथम विजेता को 51 हजार, द्वितीय विजेता को 31 हजार और तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 11 हजार रूपए प्रदान किया जाएगा। डॉ. मणि मेखला शुक्ला ने बताया कि परीक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विजय शर्मा के निदेशन में संपन्न कराई गई। परीक्षा के दौरान सहायक प्राध्यापक अंबेई देव और विभागीय चौक की महत्वपूर्ण भूमिका में तैनात रहे।

गौ विज्ञान परीक्षा की नोडल अधिकारी डॉ. मणि मेखला शुक्ला ने बताया कि वह प्रतिभागिता महाविद्यालयी स्तर के बाद जिला और फिर राज्य स्तर पर आयोजित कर प्रथम विजेता को प्रमाणपत्र के साथ 31 सी रूपए, द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 21 सी रूपए और तृतीय श्रेणी पर आने वाले प्रतिभागी को 11 सी रूपए प्रदान किया जाएगा। जबकि राज्य स्तर पर प्रथम विजेता को 51 हजार, द्वितीय विजेता को 31 हजार और तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 11 हजार रूपए प्रदान किया जाएगा। डॉ. मणि मेखला शुक्ला ने बताया कि परीक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विजय शर्मा के निदेशन में संपन्न कराई गई। परीक्षा के दौरान सहायक प्राध्यापक अंबेई देव और विभागीय चौक की महत्वपूर्ण भूमिका में तैनात रहे।

"जिला न्यायालय दुर्ग व तालुका न्यायालयों के ई-सेवा केंद्रों के सुचारु संचालन के लिए कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण



नई दृष्टि/दुर्ग

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के दिशा-निर्देशन एवं मनीषी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के मार्गदर्शन में जिला स्थापना, दुर्ग में संचालित ई-सेवा केंद्रों के सुचारु, प्रभावी एवं परवर्द्ध संचालन के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त क्रम में दिनांक 27 जनवरी 2026 को जिला न्यायालय दुर्ग तथा तालुका न्यायालय पाटन, भिलाई-3 एवं धमपा में संचालित ई-सेवा केंद्रों के वेबहतर संचालन हेतु जिला स्थापना एवं तालुका न्यायालयों के

नायब नाज़िर एवं ई-सेवा केंद्रों में पदस्थ कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्यूटीकरण कमिटी के अध्यक्ष पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को अध्यक्षता में तथा नोडल अधिकारी प्रथम अतिरिक्त, प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग में मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में सहायक प्रोग्रामर श्री तर्पण कुमार चंद्रकर एवं तकनीकी सहायक श्री ऋषिभक्त ताराई ई-सेवा केंद्र से संबंधित तकनीकी एवं व्यवहारिक जानकारीयों

विस्तारपूर्वक प्रदान की गई। प्रशिक्षण के दौरान ई-सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न डिजिटल सेवाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक एवं आमजन को अधिकतम लाभ पहुंचाने के तरीकों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा कि न्यायालय में आने वाले पत्रकारों एवं अधिकारियों को उनके प्रकरणों से संबंधित आवश्यक जानकारी जैसे संबंधित न्यायालय का नाम, आगामी सुनवाई की तिथि, आदेश की स्थिति, प्रकरण की वर्तमान स्थिति आदि

भिलाई बिरादरी 2 फरवरी को मिलजुलकर बोलेगी 'थैक्यू भिलाई'

भिलाई आयोजन आगामी 2 फरवरी (सोमवार) को शाम 4 बजे से पानियनर मॉन्यूमेंट, सिविक सेंटर, भिलाई में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन लगातार आठवें वर्ष किया जा रहा है। शायप फाउंडेशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2 फरवरी 1925 को भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के परिणामस्वरूप भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, जिससे भिलाई शहर का अस्तित्व और उसकी विशिष्ट संस्कृति विकसित हुई। इस

ऐतिहासिक दिवस की वरगांठ को अपने शहर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से हर वर्ष थैक्यू भिलाई का आयोजन किया जाता है। आयोजन की शुरुआत इस वर्ष भी सद्भावना दीर्घ से होगी, जिसमें हर आयु वर्ग के भिलाईवासियों की सहभागिता रहेगी। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 9 विशिष्ट व्यक्तियों को 'नवत सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही शहर के विकास और सामाजिक सेवा में सक्रिय संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा तथा कुछ प्रमुख संगठनों व प्रतिनिधियों को विशिष्ट सेवा सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। आयोजन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। शायप फाउंडेशन द्वारा जानकारी दी गई कि इस वर्ष से 'थैक्यू भिलाई' आयोजन में हैरिटेज टॉक की विशेष शुरुआत की जा रही है। इस सत्र में भिलाई के इतिहास, संस्कृति, इस्पात संयंत्र, पानियनर मॉन्यूमेंट और शहर से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित प्रश्न-उत्तर आसोजित किए जाएंगे।

इन प्रश्नों के सही और प्रभावशाली उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को मंच पर ही तालुका सम्मानित किया जाएगा, साथ ही उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। यह सत्र भिलाई की विरासत को जानने-समझने और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ने का एक अनूठा अवसर होगा। इसके अतिरिक्त आयोजन स्थल पर सर्वधर्म प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रहेगी, जिनके मार्गदर्शन में उपस्थित नागरिक सामूहिक रूप से 'थैक्यू भिलाई' का उद्घोष करेंगे।

सुसाइड नोट ने खोले दर्दनाक राज, धरेलू हिंसा और परिवारिक तनाव से टूटा युवक

नई दृष्टि/भिलाई

जामुल थाना क्षेत्र में ग्राफिक डिजाइनर भोजनारायण निपाद की आत्महत्या के मामले में अब एक भावुक और चौकाने वाला सुसाइड नोट सामने आया है। नोट में मृतक ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष से जुड़ी परेशानियों, मानसिक प्रताड़ना और धरेलू हिंसा का जिक्र करते हुए आत्महत्या का कारण बताया है।

भोजनारायण ने अपने पत्र में लिखा है कि पहले दोनों के बीच गहरा प्रेम था और वे एक-दूसरे की भावनाओं को बिना थोके समझ लेते थे। लेकिन 30 दिसंबर के बाद से सब कुछ बदल गया। पत्नी ने उसका मोबाइल फोन ले लिया और कई डाटा डिलीट कर दिए, जिससे उसे शर और बढ़ गया। सुसाइड नोट में मृतक ने यह भी लिखा है कि वापस आकर पत्नी के पास रहना उसकी 'सबसे बड़ी गलती' साबित हुई। उसने खुद को धरेलू हिंसा का शिकार बताया और कहा कि पत्नी से तंता आकर वह वह कदम उठा रहा है। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी तिकेश्वरी का कुछ लोगों, विशेषकर सुनील वाम और उसके परिवार से संबंध बन गया था, जिसके चलते उनका दंपत्य जीवन पूरी तरह टूट गया।

सुसाइड नोट में मृतक ने यह भी लिखा है कि वापस आकर पत्नी के पास रहना उसकी 'सबसे बड़ी गलती' साबित हुई। उसने खुद को धरेलू हिंसा का शिकार बताया और कहा कि पत्नी से तंता आकर वह वह कदम उठा रहा है। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी तिकेश्वरी का कुछ लोगों, विशेषकर सुनील वाम और उसके परिवार से संबंध बन गया था, जिसके चलते उनका दंपत्य जीवन पूरी तरह टूट गया।

भोजनारायण ने पत्र में यह आश्चर्य भी जताई कि उसकी पत्नी पर ससुराल पक्ष का दबाव है और उसे मानसिक रूप से निर्वासित किया जा रहा है। उसने आरोप लगाया कि तिकेश्वरी को बंधक जैसी स्थिति में रखा गया है, उसका इलाज तक ठीक से नहीं कराया जा रहा और उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है।

संपादकीय

कड़ू राजनीति का राजनीतिक कोशिका

देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, स्वाभाविक है कि वह जहां भी राजनीतिक फायदा दिखेगा वह राजनीति जरूर करेगा राजनीति का नाम ही समाज को टुकड़ों में बांटने जाना है। समाज के अंदर-छेद-छेद टुकड़ करेगा है। उसको जाति में बांट कर रखना है, उसको अड़ना-पिछना में बांट कर रखना है। लसंगों और बंदित में बांटना कर रखना है। वही देश में बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, साथ संत हैं, वह समाज को जोड़ने का काम करते रहते हैं। वह कहते हैं कि तुम सब जाति में मत बांटो, तुम सब हिंदू हो, तुम सब सनतानी हो। वह दोनों काम देश में चलता रहता है, एक तरफ देश व समाज को जोड़ने का काम चलता रहता है तो एक तरफ मौला मिलते ही समाज को तोड़ने का काम शुरू हो जाता है। यूजीसी के कुछ नए नियम इन दिनों चर्चा में हैं, उसे लेकर जो कुछ कहा जा रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि अड़ानों व बर्बादों को फिर एक बार भड़काने की कोशिश हो रही है।

कई सालों बाद अगुओं को सामान्य वर्ग के लोगों को यूजीसी के कुछ नए नियमों को लेकर भड़काने की कोशिश की जा रही है। उनमें मुख्य पैदा करने की कोशिश की जा रही है। टीक विसा ही गुस्ता जैसा एक समय मंडल आयोग की रिफार्मिशन लागू करते समय पैदा हुआ था। इसके तहत ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था करने विरोध देश भर में हिंसक विरोध हुआ था। सामान्य वर्ग के युवाओं ने विरोध में आमदवाह भी किया था। इन दिनों यूजीसी की देश भर की युनिवर्सिटी व कालेजों में होने वाले जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए नए नियम बनाए हैं। इस नये नियम के अनुसार जातिगत भेदभाव के मामले में एक कैटेगरी बनाई जाएगी जो एससी, एसटी ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनीं। तब समय में उसका समाधान करने वाला। इकमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना अनिवार्य है। कमेटी का काम केपस में बराबरी का माहौल बनाना है और ओबीसी के लिए योजनागत लागू करना है। यूजीसी का यह नियम बनाया इसलिए गया है कि जातिगत भेदभाव की समस्या का समाधान हो सके। कुछ लोग इस समस्या के समाधान की कोशिश को ही वह कहकर समाधान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सामान्य वर्ग के लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि वह नियम सही हैं व सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ है। इन्होंने जा रहा है कि नियमों में सिर्फ एससी, एसटी ओबीसी के खिलाफ भेदभाव को बताने करी है। जनरल लोगों के खिलाफ भेदभाव को भेदभाव ही नहीं माना जाएगा, सामान्य वर्ग के लोगों को खराब जा रहा है कि इन नियमों का प्रधान उद्देश्य कोई भी छात्र सामान्य छात्र को फंसा सकता है, उसकी शिक्षा में बाधा पैदा कर सकता है। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन अभी से नियमों का विरोध शुरू हो गया है। जब होगा तब इस बात को जोशोर से उठाया जाता तो यूजीसी इस समस्या के समाधान का भी कोई रास्ता निकालता है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मदेव प्रधान ने इस मामले में साफ तौर पर कहा है कि यूजीसी के नए नियमों से किसी को भी किसी प्रकार की उपनिवेश का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद भी छात्रकत यूजीसी में यूजीसी के नए नियमों का सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है। या कहा जा सकता है कि राजनीति शुरू कर दी गई है। इस मामले को दृष्टि देने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अधिनियम 1952 के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इसका सामना वर्ग के लोगों को इस मामले में भड़काने की कोशिश है, उसकेसने की कोशिश है सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए। दूसरे सूर्य में भी अपने पंच से इसी तरह इस्तीफा देकर विरोध जताए। वह सामान्य वर्ग के लोगों का खुद को ताने बाने की कोशिश है। वह जाने की कोशिश है कि मैं जो कर रहा हूँ, वही सही है, मैंने जो किया है वही सही है।

इस मामले में अभी वह राजनीतिक दल सामने नहीं आए हैं क्योंकि वह जानते हैं कि किसी एक का पक्ष लेने से उनको राजनीतिक नुकसान हो सकता है लेकिन चुनने से चुनने से कि यह जो किया जा रहा है कि इसलिए किया जा रहा है कि यूपी के चुनाव में इसे मुझ बनकर भाजपा को नुकसान पहुंचाया जाए। सब जानते हैं कि सामान्य वर्ग के लोग भाजपा को ज्यादा वोट देते हैं, इसलिए सामान्य वर्ग को भाजपा के खिलाफ करने के लिए यह वक्तव्य जा रहा है। इस अगर सरकार यूजीसी के नियम बदलती है तो राजनीति करने वाले सरकार को दलित, पिछड़ा विरोधी बनाएँ और सरकार नियम नहीं बदलती है तो भाजपा को वोट बैंक सामान्य वर्ग को भाजपा के खिलाफ भड़काना जाएगा कि देशों युग लोग भाजपा को वोट देते हैं और भाजपा सरकार तुम्हारे खिलाफ नियम बनाती है। यूजीसी के नए नियमों का विरोध सरकार को मुश्किल में डालने के लिए किया जा रहा है।

संदेश नाकारात्मक है



जिस समय मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत से वार्ता अंतिम दौर में है और इसी हफ्ते उसीकी घोषणा की आशा है, जीएपीसी के तहत मिली छूट की सुविधा हटाने के ईयू के कदम से नकारात्मक संदेश गया है।

भारतीय उत्पादों से सामान्यीकृत प्राथमिकता प्रणाली (जीएपीसी) के तहत मिली छूट को हटा लेने के यूरोपीयन युनिवर्न (ईयू) के फैसले पर केंद्र ने इसका विरोध किया। न्यायत पर केंद्र ने इसका ज्यादा असर नहीं होगा। सरकार का दावा है कि इससे भारत के सिर्फ 2.66 प्रतिशत निर्यात प्रभावित होंगे। जबकि ईयू मुख्यालय से अर्थ अधिकारी में बताया गया है कि जीएपीसी छूट हटाने से से वस्त्र, प्लास्टिक, धातु, इंजीनियरिंग सामग्रियों सहित लगभग 87 फीसदी भारतीय निर्यात यूरोपीय बाजार में बालांशहीन या निर्यातमान जैसे प्रतियोगी देशों के उत्पादों की तुलना में महंगे हो जाएंगे। जिस समय मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत से वार्ता अंतिम दौर में है और इसी हफ्ते उसकी घोषणा की आशा है, बेवक ईयू के इस कदम से नकारात्मक संदेश गया है।

कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने देश के नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की

कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने देश के नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है। टंप प्रशासन द्वारा कनाडाई उत्पादों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी को देखते हुए ये अपील की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जोनाथन टंप ने कनाडा को वैतानवी देते हुए कहा है कि यदि वह चीन के साथ व्यापार समझौता करता है तो कनाडा पर सी कोसदी टैरिफ लगाएंगे। टंप की इस चेतावनी के बाद एक मीडियो संदेश में कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 'कनाडा की अर्थव्यवस्था पर बाहरी दबाव है। ऐसे में कनाडा के लोगों के पास यही रास्ता है कि वो ही सामान खरीदें, जो कनाडा में बने हैं। दूसरे देश बना करते हैं, हम उस से निर्यात नहीं कर सकते। जो हमारे नियंत्रण में है उसपर फोकस करें। हम ही कनाडा के सबसे अच्छे ग्राहक हैं और हमें कनाडा से बने उत्पाद खरीदने चाहिए ताकि देश को मजबूत बनाया जा सके। अमेरिका और कनाडा दोनों देशों के बीच टैरिफ के दोबारा सत्ता में आने के बाद तत्काली तब और बढ़ गई जब टंप ने कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही, हालांकि पिछले साल कार्नी ने क्लार्ट हाउस में टंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ राक्षी में कहा था कि कनाडा बिकाने नहीं है।



आयोग मधु

आज जो हालात कनाडा के साथ हैं, वही दुनिया के कई अन्य देशों के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति टंप कभी भारत तो धमकी देते हैं तो कभी चीन को। ग्रीनलैंड का स्वतंत्र करने वाले देशों को भी इस तरह की उभरी हाल में धमकी आई है। इस तरह की धमकी एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है। बड़ी शक्तियों छोटी शक्ति और देशों को दबाकर रखना चाहती हैं। वे छोटे और समग्र देशों को अपना गुलाम बनाकर रखना पसंद करती हैं। अपने पर निर्भर बनाए रखना चाहती हैं। इस तरह के आसना खराब को भारत ने पहले ही भांप लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी समय से स्वदेशी अपनाने पर वैसे ही नहीं जोर दे रहे। भारत में स्वदेशी का विचार कोई नया नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नया आयाम दिया है। वोक्लर फोर लोकल का नारा देते हुए उन्होंने देशवासियों से भारतीय उत्पादों को अपनाने और उन्हें वैश्विक बजार का आह्वान किया है। यह दृष्टिकोण केवल आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है। जब हम अपने देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, तो हम न केवल अपनी

अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करते हैं। दूसरे देशों पर हमारी विभक्त कानों। उनका हम पर दबाव कम होगा। प्रधानमंत्री को समझने के लिए हमें महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन को याद करना होगा। गांधीजी ने स्वदेशी को केवल आर्थिक रणनीति के रूप में नहीं देखा था, बल्कि इसे स्वराज और आत्मनिर्भरता का व्यापक दर्शन का हिस्सा माना था। उनका मानना था कि जब तक हम आर्थिक रूप से परतंत्र रहेंगे, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और चरखे से बने वस्त्रों को अपनाने पर जोर दिया। गांधीजी के लिए चरखा केवल कपड़ा बनाने का साधन नहीं था, बल्कि वह आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक था। द अरबाज अंग्रेजों के शासन से पहले जरूरत का सारा सामान हमारे यहां गांवगांव और आसपास में पैदा होता है। जरूरत का काफी सामान हम अपने घर तैयार कर लेते थे। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बड़े-बड़े उद्योग लामाकर खत्म कर दिया। महात्मा गांधी ने स्वदेशी का महत्व समझा। उनका स्वदेशी आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण स्थिराण बना। उन्होंने लोगों को समझाया कि जब हम विदेशी वस्तुओं को उपयोग करते हैं, तो हम

न केवल अपने देश की संर्भक्ति को बाहर भेज रहे हैं, बल्कि अपने कारीगरों और श्रमिकों की भी बेरोजगार कर रहे हैं। उनका मानना था कि प्रत्येक भारतीय को अपने गांव और अपने देश में बनी वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह विचार इतना प्रभावशाली था कि लाखों भारतीयों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी को अपनाया। यह आंदोलन केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि इतने राष्ट्रिय चेतना को जगाने और लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की वैश्वीकृत दुनिया में स्वदेशी को अंधाधुंध लागू करने और महत्व प्राप्त कर रही है। कनाडा पर टंप की टैरिफ धमकी यह दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किना अनिश्चित और राजनीतिक रूप से प्रभावित हो सकता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश पर आर्थिक दबाव बनाता है, तो व्यापार शुल्क एक प्रमुख स्थिराण बन जाता है। ऐसी स्थिति में जो देश अपनी शर्तु उत्पादन क्षमता को मजबूत रखते हैं, वे बेहतर तरीके से इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यही कारण है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों से देश में बने उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया है। भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल इसी दिशा में एक व्यापक और दूरदर्शी कदम है। इस अभियान का उद्देश्य केवल आयात को कम करना नहीं है, बल्कि भारत को

विनिर्माण, नवाचार और तकनीकी विकास का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार कहा है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ आत्मनिर्भर होना नहीं है, बल्कि वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय और मजबूत भागीदार बनना है। जब भारतीय उत्पाद गुणवत्ता और नवाचार में उत्कृष्ट होंगे, तो वे न केवल शर्तु बाजार में सफल होंगे बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बनाएंगे। स्वदेशी को अपनाना का अर्थ यह नहीं है कि हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार का वैश्विकरण के खिलाफ हैं। बल्कि वह एक संतुलित दृष्टिकोण है जो शर्तु उद्योगों को मजबूत करते हुए वैश्विक बजार में भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। जब हमारे उत्पाद मजबूत होंगे, तो हम बेहतर शर्तों पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग ले सकेंगे। यही कारण है कि भारत मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से शर्तु उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। स्वदेशी उत्पादों को अपनाने से रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश हम स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं, तो हम अपने देश के कारीगरों, किसानों, छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों की आजीविका का समर्थन करते हैं। भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, स्वदेशी

उत्पादों को बढ़ावा देना लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। छोटे और मध्यम उद्योग जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, तभी फल-फूल सकते हैं जब उन्हें पर्याप्त शर्तु बाजार मिले।

पर्यावरण को हित से भी स्वदेशी उत्पादों का महत्व बढ़ जाता है। जब हम स्थानीय शर्तु उत्पादन करते हैं, तो हम अपने स्थानीय उत्सर्जन कम होता है। साथ ही, स्थानीय उत्पादन अवसर पारंपरिक और टिकाऊ तरीकों का उपयोग करता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। गांधीजी ने भी कहा था कि पृथ्वी के पास हर व्यक्ति को जरूरत की पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। स्वदेशी की अवधारणा इसी सिद्धांत पर आधारित है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां व्यापार युद्ध और आर्थिक राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, स्वदेशी की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। कोविड-19 महामारी ने भी हमें सिखाया कि अत्यधिक आयात निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं टूट गईं, तो कई देशों को आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ा। भारत ने इस संकट से सीख लेते हुए दबाओ, स्थितिस्था उपकरणों, और अन्य आवश्यक वस्तुओं को शर्तु उत्पादन को बढ़ावा दिया है। कि भी हम न मार्क बनाते थे। न सेनेटइज्जर, न अपने आयात। कोरोना महामारी ने हमने कोशिश की और आत्म निर्भर होनी पड़ी। देश की बनी करतव्य वैश्वीकन कई देशों को दी।

स्वदेशी को सफल बनाने के लिए एक सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। इसके लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। जब हम खरीदारी करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि हमें उत्पाद कहाँ बना है और किसके द्वारा बनाया गया है। छोटे निर्यात जैसे स्थानीय बाजार से खरीदारी करना, हस्तनिर्माण को बढ़ावा देना, और भारतीय उत्पादों को चुनना, सामूहिक रूप से सच्चा प्रभाव डाल सकते हैं। यह केवल आर्थिक नियम नहीं है, बल्कि वह हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी का प्रश्न है।

सरल नहीं पर प्रभावशाली थे, आदर्शवादी नहीं पर निर्णायक थे अजित पवार

नीरज कुमार द्वे

महाराष्ट्र की राजनीति को आज तब गहरा आघात लगा जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में विधान हदसरे में निधन हो गया। लैटिंग के दौरान विधान में आई तकनीकी खराबी के बाद वह दुर्घटना हुई। हदसरे की खबर फैलते ही राज्य भर में शोक की लहर दौड़ गई। देखा जाये तो अजित पवार महाराष्ट्र के उन नेताओं में थे जिन्होंने सच के केंद्र में रहते हुए भी जमीन से नाना नहीं तोड़ा। वह भले ही कभी मुख्यमंत्री न बने हों, लेकिन राज्य में सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री रहने का इतिहास उनके नाम दर्ज है।



छह बार उपमुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने वाले अजित पवार ने अलग-अलग सरकारों में अपनी प्रशासनिक पकड़ और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा। बारामती में अजित पवार की राजनीति का सबसे बड़ा प्रमाण उनका काम खुद था। वह उन गिने गिने नेताओं में थे जिन्होंने लिए अपना खुद का चुनाव प्रचार एक औपचारिकता पर था। विधानसभा चुनावों में वह हमेशा सामने आया। नानांकन दालिख करते थे, लेकिन उनके बाद बारामती की गलियों में बनाए ही के कभी उन्हें प्रचार करते देखा गया। जनता जानती थी कि किससे वोट देना है, इसलिए जनता ही उनका प्रचार करती थी। अजित पवार का भरोसा नापें पर नहीं, काम पर था। इसी आत्मविश्वास के चतुते वह बारामती से निर्धित रहकर राज्य के दूसरे इलाकों में पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार में जुट जाते थे। बारामती उनके लिए सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं था, वह उनका कर्मभूमि था, जहां उन्होंने यह साबित किया कि वह विकास पवती है। तो नेता को खुद बोलेने की जरूरत नहीं पड़ती।

अजित पवार ने 1982 में सहकारी क्षेत्र से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वह चीनी मिल के बोर्ड में चुने गए और यहीं से बारामती की राजनीति में उनकी जड़ें मजबूत होती गईं। 1991 में वह गुणे जिला क्षेत्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और उसी वर्ष बारामती से लोकसभा सांसद चुने गए। बाद में उन्होंने ये संसद पद शरार के लिए खाली की। इसके बाद वह बारामती से सात बार विधायक बने। उनके परिवार में पत्नी सुनेत्रा पवार और दो पुत्र हुए और पाथ हैं। सरकारों से सत्ता तक का उनका सफर बारामती से शुरू हुआ और वहीं समाप्त हुआ। राष्ट्रपति काँग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाले टुपे चुनाव आयोग ने पार्टी का मूल नाम और चुनाव चिन्ह सौंपा था, यह गुट भाजपा के नेतृत्व वाले महायुक्ति से साया जुटा। वहीं उनके चाचा और पत्निसने तारा शरद पर ने अलग हर करणपत्नी-एएसपीका का नेतृत्व संभाला। वे विभाजन महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे भावनात्मक और निर्णायक मोड़ माना गया।

दोनों पक्षों का विवाद अदालत के दरवाजे तक पहुँचा लेकिन हाल के दिनों में पवार परिवार के एकजुट नजर आ रहा था। हम आपको याद दिला दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ उतार कर पारिवारिक और राजनीतिक दोनों में लौटापन ला दिया था, लेकिन समय के साथ उन्होंने यह आश्चर्य करण किया था कि वह फैसला एक भूल था। राजनीति के उस कडवर दौर के बाद हालिया निकाय चुनावों में उन्होंने जिस परिपक्वता का परिचय दिया, वह उनके व्यक्तित्व का दूसरा और अधिक मानवीय रूप सामने लाता है। शरद पवार की मौत के साथ गटबंधन कर दोनों पत्नीसौती को एक बच पर लाने की पहल उन्होंने खुद की थी। वहन सुप्रिया के साथ संयुक्त प्रेरकक्रॉस में उन्होंने साफ कहा था कि परिवार में कोई मतभेद नहीं है और जनता चाहती है कि दोनों दल साथ मिलकर काम करें। यह सिर्फ ज्वलीकृत बयान नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक स्वीकृति थी। देखा जाये तो अपने पिछले पक्ष में अजित पवार कम से कम इतना तो कर ही गए कि उन्होंने परिवार से सुलह कर ली, टूटे रिश्तों को जोड़ दिया और महाराष्ट्र की राजनीति को यह संकेत दे दिया कि उकरार नहीं, संवाद ही आका रास्ता है।

अपने लंबे राजनीतिक जीवन में अजित पवार ने पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जैसे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। गठबंधनों के बदलते दौर में भी अपने उभयपक्षीय और अस्वर भाषण रखना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पुँजी रही। अजित पवार सिर्फ केंद्र और महाराष्ट्र में सत्ताइत पड़सारे के प्रमुख पक्षक थे इसलिए उनका निधन बड़ा राजनीतिक नुकसान भी है। देखा जाये तो अजित पवार का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, यह उस राजनीतिक शैली का अंत है जो चुपचाप काम करने में कर्तव्य रखती थी। उनकी राजनीति प्रशासनिक पकड़, अकड़ों की समझ और सत्ता की नस पहचानने की कला से असी थी। शरद पवार की विशाल छाया में राजनीति शुरू करना आसान था, लेकिन उस छाया से

निकलकर अपनी पहचान बनाना बेहद कठिन था। अजित पवार ने यह कठिन रास्ता चुना। वह हमेशा इस केंद्र में रहे कि उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाए या एक स्वतंत्र नेता के रूप में। शायद इसी बेचैनी ने उन्हें बार-बार जोखिम लेने के लिए प्रेरित किया।

2023 की वह सुबह भारतीय राजनीति के सबसे नाटकीय क्षणों में गिनी जाती है जब उन्होंने सरकार सत्ता का सामंजसिक हल दिया था। उनकी कार्रवायिका सुई, अविश्वास भी पैदा हुआ, लेकिन यह भी सच है कि उसी क्षण ने उन्हें निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया। बाद में चुनाव आयोग का फैसला उनके पक्ष में आया इस बात का संकेत था कि राजनीति में साहस कई बार वैतनता भी दिला देता है। अजित पवार का राजनीति नैतिकता के आदर्शों की किताब से कम और सार्थक की जमीन से ज्यादा निकली थी। यही कारण है कि वह अलोचकों के निशाने पर भी रहे और समर्थकों के भरपूर का केंद्र भी बने। वह जानते थे कि सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन प्रयास बनाया जा सकता है। उन्होंने यह किया। विभिन्न लोकप्रभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान मैं खुद दृष्टि कि वह समर्थकों और कार्यकर्ताओं के निरन्तर करीब रहते हैं और सबकी जाति ध्यान से सुनते हैं। यही कारण था कि बारामती में खासतौर पर अजित दाद के नाम का बोधवाला हर जगह देखने को मिलता है।

आज जब उनका जाना अयाचक और असमय हुआ है, महाराष्ट्र की राजनीति एक खालीपन महसूस कर रही है। यह खालीपन सिर्फ एक कानूनी, उस अनुभव का है जो देशकों में गड़ा जाता है। आने वाले समय में यह सवाल और तीखा होगा कि क्या कोई नया रहकार से सत्ता तक देस रास्ते को फिर उसी धार और हड़ता से तय कर पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अजित पवार की विरासत विरोधभाषियों से पूरी रही, लेकिन शायद यह उनको सच्ची पहचान थी है। वह शरद नहीं थे, पर प्रभावशाली थे। यह आदर्शवादी नहीं थे, पर निर्णायक थे। और इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में उनका नाम लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

बुजुर्गों की सेवा में 'समय बैंक'

विनित नारायण

रिव्दरलैड में इस कार्यक्रम की शुरुआत बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और उनकी देखभाल की जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, स्वस्थ और संवाद करने में कुशल व्यक्ति बुजुर्गों की मदद करते हैं, जैसे खरीदारी करना, कमा साफ करना, सूरज की रोशनी में बाहर ले जाना या बस वातचाल करना। प्रत्येक घंटे की सेवा को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के व्यक्तिगत 'समय खाते' में जमा किया जाता है।

भारत जैसे देश में, जहां बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और परंपरिक परिवार संरचना कमजोर पड़ रही है, बुजुर्गों की देखभाल एक बड़ी चुनौती बन गई है। सरकारी पेंशन योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तो हैं, लेकिन वे अक्सर अपर्याप्त साबित होते हैं। ऐसे में, रिव्दरलैड की 'समय बैंक' अवधारणा एक प्रेरणादायक मॉडल प्रस्तुत करती है, जो न केवल बुजुर्गों की देखभाल को सुनिश्चित करती है बल्कि समाज में सहानुभूति और सामुदायिक भावना को भी मजबूत करती है। यह अवधारणा, जो रिव्दरलैड के संघीय सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित की गई है, युवाओं को बुजुर्गों की सेवा करने का अवसर देती है और बदले में उन्हें भविष्य में खुद की देखभाल के लिए 'समय' जमा करने की अनुमति देती है। भारत सरकार को इस मॉडल को अपनाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक मूल्यों से मेल खाता है और आर्थिक बोझ को कम कर सकता है। रिव्दरलैड में इस कार्यक्रम की शुरुआत बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और उनकी देखभाल की जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, स्वस्थ और संवाद करने में कुशल व्यक्ति बुजुर्गों की मदद करते हैं, जैसे खरीदारी करना, कमा साफ करना, सूरज की रोशनी में बाहर ले जाना या बस वातचाल करना। प्रत्येक घंटे की सेवा को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के व्यक्तिगत 'समय खाते' में जमा किया जाता है। यह व्यक्ति खुद बुजुर्ग हो जाता है या बीमार पड़ता है, तो वह इस जमा समय को निकाल सकता है और अन्य स्वस्थसेवक उनकी देखभाल करे। यह प्रणाली के केवल पैसों की बचत करती है बल्कि मानवीय संबंधों को भी मजबूत करती है।

कल्पना कीजिए, एक युवा व्यक्ति जो सहाह में दो बार दो घंटे बुजुर्गों की सेवा करता है, एक साल बाद, 'समय बैंक' उसके कुल सेवा समय को गणना करता है और उसे एक 'समय बैंक' काई देता करता है। इस काई से वह भविष्य में 'समय और समय' खर्चा निकाल सकता है। आज, समय पर बुजुर्गों की मिलाता है, जो प्रोत्साहन का काम करता है। रिव्दरलैड में यह प्रथा अब सामान्य हो गई है और सरकार ने इसे समर्थन देते हुए कानून भी पारित किया है। यह मॉडल पेंशन व्यवस्था को कम करता है और समाज को अधिक सहयोगी बनाता है। भारत में इस अवधारणा को लागू करने की संभावनाएं अपार हैं। एक अनुमान के तहत, 2030 तक हमारे देश में बुजुर्गों की आबादी 19 करोड़ से अधिक हो जाएगी और कई परिवारों में वृद्ध शहरी में बुजुर्गों हैं, जिससे सुरक्षा अकेले रह जाते हैं। पारंपरिक रूप से, भारत में बुजुर्गों की देखभाल परिवार की जिम्मेदारी रही है, लेकिन आधुनिकीकरण ने इस संरचना को प्रभावित कर दिया है। 'समय बैंक' जैसे सामूहिक युवाओं को प्रोत्साहित कर सकता है कि वे बुजुर्गों की सेवा करें और बदले में उन्हें सुरक्षा का आश्वासन मिले। यह न केवल सरकारी संसाधनों पर दबाव कम करेगा बल्कि बेरोजगार युवाओं को सार्थक कार्य प्रदान करेगा।

उदाहरण के लिए, रिव्दरलैड की एक कर्मिका से प्रेरणा लेते। वहां एक 67 वर्षीय स्वस्थशुभ शिल्पिका क्रिटिना एक 87 वर्षीय बुजुर्ग की देखभाल करती थी। उन्होंने कहा कि वह पैसों के लिए नहीं, बल्कि 'समय बैंक' में समय जमा करने के लिए ऐसा कर रही थी। जब वे खुद भाव्य हुईं, तो 'समय बैंक' ने दूरत एक नर्सिंग कार्यकर्ता भेजा जो उनकी देखभाल करता था। कुछ दिनों में वे स्वस्थ हो गईं और फिर से सेवा में लगे गईं। यह कहानी दशाती है कि कैसे यह प्रणाली व्यापकरीक और प्रभावी है। भारत में भी, यदि केवल एक सरकारी मिशनरू ऐसा कार्यक्रम शुरू करें, तो लाखों बुजुर्गों का जीवन बेहतर हो सकता है। हालांकि, भारत में इसे लागू करने से पहले कुछ चुनौतियों पर विचार करना जरूरी है। सबसे पहले, कार्यक्रम की लक्ष्यताओं को सुनिश्चित करना होगा। जहां सेवा घंटे को रिक्त किया जा सके। आधार काई और डिजिटल इंडिया जैसे मीजुट सिस्टम इसमें मदद कर सकते हैं। दूसरा, स्वस्थसेवकों की ट्रेनिंग करना है, मानि वे बुजुर्गों की भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को समझ सकें। तीसरा, दुरुयोगों को रोकने के लिए परामर्श प्रक्रिया बनानी चाहिए, जैसे कि समय निगरानी से समय पहचाना जा। इसके अलावा, प्रमाणों को सिकुड़ने की कमी एक समस्या हो सकती है, इसलिए ऑफलाइन मॉड भी विकसित किया जाना चाहिए।



फोकस

ग्वालियर से लाई जा रही चंद्रखुरी के लिए श्रीराम की नई प्रतिमा

रायपुर। चंद्रखुरी स्थित कोशल्या माता धाम में जल्द भगवान श्रीराम की नई प्रतिमा लगाई जाएगी। ग्वालियर में नई प्रतिमा बनकर तैयार है, जिसे लाने के लिए टीम ग्वालियर निकल चुकी है। कुछदिन में श्रीराम की प्रतिमा लाकर शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाएगा। पर्यटक एवं संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि छठछठ आर्यनाइजेशन की ओर से कोशल्या माता धाम में प्रतिमा लगाई गई थी। जो प्रतिमा बनी थी, वह प्रयोग में नहीं होने के कारण हमने बता दिया था कि यह प्रतिमा हमें मंजूर नहीं है। इसलिए वह प्रतिमा हमें रिप्लेस करके चाहिए। चंद्रखुरी स्थित कोशल्या मंदिर में भगवान श्री राम की बनवासी स्वरूप वाली 51 फीट ऊंची यह प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस प्रतिमा को वहां वर्तमान में स्थापित भगवान श्री राम की प्रतिमा की जगह पर ही स्थापित किया जाएगा। इस प्रतिमा के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के प्रसिद्ध राष्ट्रपति सम्मानित मृत्तिकार दीपक विश्वकर्मा को निर्देश दिए थे। इसके बाद ग्वालियर से इस्टीमेट ऑफ एंड क्राफ्ट सेंटर पर मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो अब पूरा हो गया है। प्रतिमा की एक खासियत यह भी है कि इसमें 108 मनके रत्नज के बनावे गए हैं।

4 नक्सलियों ने किया सरेंडर

सुकमा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की कमान लगानार ट्टर रही है। नक्सल संगठन को फिर बड़ा झटका लगा है। सुकमा जिला मुख्यालय में शुरूवार को 8 लाख रुपए के इनामी 4 नक्सलियों ने हथियार के साथ पुलिस अधिकारियों के समक्ष सरेंडर किया है, इन्होंने एपीएम रैंक के नक्सली शामिल हैं। सरेंडर करने वालों में 2 महिला नक्सली हैं। इस संगठन SLR, INSAS, 303, 315 राफल व एम्बुशनर जमा किया गया है।

जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां आज ढोल-मांदर की थाप बजती है- मंत्री कश्यप

जिला स्तरीय एक दिवसीय 'जनजातीय गौरव और परंपरा का पर्व बस्तर पंडुम' का हुआ शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु/ रायपुर

बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और जनजातीय अस्मिता को सहेजने एवं संवारेने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मां दंतेश्वरी मंदिर के पावन प्रांगण में जिला स्तरीय बस्तर पंडुम का भाव आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बस्तर की लोकसंस्कृति, परंपरिक कला, नृत्य, संगीत एवं रीति-रिवाजों की जीवंत झलक देखने को मिली, जिसने उपस्थित जनसमूह को बस्तर की आत्मा से जोड़ दिया। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर बदल रहा है, बस्तर की तस्वीर बदल रही है और देश-विदेश में बस्तर की एक नई पहचान बन रही है। जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां आज ढोल-मांदर की थाप बजती है।

बस्तर की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करना जिला स्तरीय बस्तर पंडुम के शुभारंभ अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि बस्तर को समृद्ध



बस्तर पंडुम में बस्तर के बदलते स्वरूप को दर्शाती है

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बस्तर पंडुम के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस आयोजन में 12 विधियों में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने बस्तर की संस्कृति को सहेज और जीवित रखा है, और यह हम सभी का कर्तव्य है कि इस सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि पहले बीजापुर, सुकमा और देवड़ा में जहां कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां ढोल-मांदर की थाप सुनाई दे रही है, जो बस्तर के बदलते स्वरूप को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने कितानों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि पूर्वजों से मिली संस्कृति को उसकी पहचान बनानी है।

संस्कृति, परंपराओं और विरासत को सहेजना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत देवड़ा जिले से हुई है और उनके जीवन का आधा से

अधिक समय यहीं बीता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साव की मंशानुसार बस्तर की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम का

पहले अति संवेदनशील जिले आज आकांक्षी जिले में शामिल

श्री कश्यप ने कहा कि अब बस्तर से नवलवादा समाप्ति की ओर है और यह क्षेत्र एक समृद्ध एवं विकसित बस्तर के रूप में आगे बढ़ रहा है, जो जिले पहले अति संवेदनशील कहालते थे, वे आज प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों में शामिल हैं। उन्होंने युवा वर्ग से बस्तर के पारंपरिक गीत, संगीत जैसे 'आया माओ दंतेश्वरी' और 'साय रेता' जैसे पारंपरिक गीतों को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म में फॉलो कर प्रचार-प्रसार करने को आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने जिला स्तरीय बस्तर पंडुम के स्टर्ली का निरीक्षण कर पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया।

आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। मां दंतेश्वरी मंदिर, ढोलकाल, बारसूर, चित्रकूट और तीरथाढ़ जैसे अनेक प्रमुख पर्यटन स्थल

बस्तर की पहचान हैं। यह अवसर पर सदस्य छग राज्य महिला आयोग श्रीमती जोत्सनी मंडावी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविन्द कुंजाम, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती

छात्रों के मलखंब के प्रदर्शन ने लोगों का मन मोहा

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रस्तुति के क्रम में मुलाकोडा पोटाकेविन-2 के छात्रों ने मलखंब विधा में साहसिक करतब करते हुए लोगों को तालियां बजाने के लिए प्रभावित कर दिया। अपने फुटी और कलाबाजियों से मंत्रमुग्ध करते हुए छात्रों ने मलखंब का अद्भुत प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ग्राम मोखपाल के नरक दलों ने पारंपरिक नृत्य तथा ग्राम मड़से के कलाकारों ने टेढ़े ग्रामीण हाट बाजार के जननिवासी की जीवंत प्रस्तुति दी। इसके अलावा जगदलपुर से आए बादल एकडमी से आए कलाकारों की प्रस्तुतियों भी सरहनीय रही।

पावल गुना, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता भास्कर, नगर पालिका उपाध्यक्ष केलशा मिश्रा, जिला पंचायत एवं जनपद के जनप्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ सहित अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, सर्व समाज प्रमुख उपस्थित रहे।

सुर्खियां बटोरने के लिए बाघों का आयात करने को तैयार वन विभाग, परंतु अपने ही स्वस्थ बाघ को छोड़ना भूला

नितिन सिंघवी ने वन विभाग की उदासीनता पर उदाए गंभीर सवाल

नई दृष्टिबिंदु/ रायपुर

छत्तीसगढ़ वन विभाग शीघ्र ही मध्य प्रदेश से बाघों का आयात कर उन्हें गुरु घासीदास-तमोर पिगला टाइगर रिजर्व तथा उदती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में छोड़ने की तैयारी में जुटा है। इस उद्देश्य से दोनों टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार प्रजातियों—हिण्डा आदि—को प्रदेश के विभिन्न विडिघाघरों तथा अटारी स्थित नंदवन जंगल सफारी से लाकर छोड़े जाने की भी योजना बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, गुरु घासीदास-तमोर पिगला टाइगर रिजर्व में आयातित बाघ को सॉफ्ट रिलीज देने के नाम पर लगभग एक हेक्टेयर का बाड़ा (एन्क्लोजर) भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि वन विभाग अपने ही यहां मौजूद, पुराने, स्वस्थ ही चुके एक बाघ को जंगल में छोड़ने के प्रति पूरी तरह उदासीन बना हुआ है और उसे अब भी कैद में रखा गया है।



भूल गया वन विभाग

रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने आरोप लगाया कि विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहे जाने के बावजूद कि बाघ पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य रूप से चल-दौड़ सकता है, दो माह बीत जाने के बाद भी वन विभाग ने अब तक



इस बाघ को उसके उपयुक्त प्राकृतिक आवास में सॉफ्ट रिलीज करने की कोई दोस योजना नहीं बनाई है। न तो कोई समय-सीमा तय की गई है और न ही कोई आधिकारिक पहल दिखाई दे रही है।

चार-चार विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की जांच रिपोर्ट में क्या है

सर्जरी के चार माह बाद डॉ. पिप्लु दुबे, डॉ. संतोष आदिल, डॉ. पी. के. चंदन एवं डॉ. जे. के. जाडिया द्वारा की गई जांच में पाया गया कि बाघ पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय है। सर्जरी का घाव पूरी तरह भर चुका है और वहां दोबारा बाघ उम आया है। बाघ घाव पर पर पूरा वजन डाल पा रहा है तथा पजे की पकड़ (ग्रीप) सामान्य है। चलने, दौड़ने या जमीन से उठते समय दर्द के कोई लक्षण नहीं दिखे। बाघ दोनों पिछले पैरों पर आराम से पूरे शरीर का वजन संभाल पा रहा है। धीरे चलने पर कभी-कभी बहुत हल्की

लंगड़ाहट दिखती है, लेकिन दौड़ते समय कोई लंगड़ाहट नहीं होती। जांच के आधार पर चिकित्सकों ने निष्कर्ष दिया कि बाघ स्वस्थ है और ठीक से भोजन कर रहा है। हल्की लंगड़ाहट सर्जरी में लगाए गए इम्प्लांट या समायोजन के कारण हो सकती है, जो समय के साथ और सुधर सकती है। इस समय इम्प्लांट निकालने की कोई चिकित्सकीय आवश्यकता नहीं है। सर्जरी के चार महीने बाद बाघ की क्षमता संतोषजनक पाई गई है।

कोर्ट से क्यों छुपाई इस टाइगर की जानकारी

कोर्ट से क्यों छुपाई इस टाइगर की जानकारी रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने बताया कि नवंबर 2024 में कोरिया जिले में बाघ के शिकार के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः सज्ञान लेते हुए जलविद्युत प्राधिकार दर्ज की थी। इसके बावजूद 27.10.2025 और 10.12.2025 को कोर्ट में यह कहा गया कि किसी नई पॉघिग की घटना की जानकारी नहीं है। जबकि अप्रैल 2025 में बीजापुर वन मंडल में बाघ के पॉघिग की यह गंभीर घटना हुई थी और बाद में वही बाघ जंगल सफारी में रखा गया। यह घटना घबरावजनक संरक्षक

(वन्याणी) के सज्ञान में पूरी तरह थी। सिंघवी ने सवाल उठाया कि जब यह घटना विभाग के सज्ञान में थी, तो इसे माननीय न्यायालय से क्यों छुपाया गया और क्यों कहा गया कि किसी नई पॉघिग की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रथम मुख्य वन संरक्षक (वन्याणी) को सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल न्यायालय की अदमानना की श्रेणी में आ सकता है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण जैसे संवेदनशील विषय में पारदर्शिता की कमी को भी उजागर करता है।

उन्होंने कहा कि वन विशेषज्ञ डॉक्टर लिखित रूप में स्पष्ट कर चुके हैं कि बाघ पूर्णतः स्वस्थ है, तो एक दिन की भी अनवश्यक देरी उसके प्राकृतिक अधिकारों और वन्यजीव संरक्षण के सिद्धांतों के विरुद्ध है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि वन विभाग का स्थान मध्य प्रदेश से बाघ लाकर छोड़ने की योजना के प्रचार-प्रसार के माध्यम से सुर्खियां बटोरने में लगा है। उन्होंने सवाल किया कि जब बाघ लाने के लिए संसाधन, बाड़े और योजनाएं बनाई जा सकती हैं, तो अपने ही यहां मौजूद स्वस्थ बाघ को जंगल में लौटाने में इतनी बेरुखी क्यों? उन्होंने कहा कि इस स्वस्थ बाघ को तत्काल उपयुक्त जंगल में सॉफ्ट रिलीज किया जाय। वन्यजीव प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, बल्कि उन्हे प्राकृतिक जीवन का अधिकार दिया जाना चाहिए। अनस्थायी मामला वन्यजीव संरक्षण नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और नैतिक विफलता का उदाहरण बन जाएगा।

प्रशिक्षण वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी बारनवापारा पहुंचे प्रशिक्षु IFS अफसर, वन्यजीव प्रबंधन का लिया व्यवहारिक प्रशिक्षण

नई दृष्टिबिंदु/ बलौवाबाजार

बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षु अधिकारियों को आधुनिक तकनीकों, आईटी आधारित वन प्रबंधन तथा वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस प्रशिक्षण से भावी वन अधिकारियों ने क्षेत्रीय स्तर पर उपयोग में आने वाली तकनीकों एवं प्रबंधन प्रक्रियाओं से व्यावहारिक रूप से परिचित हुए।



कार्यपाली, उसकी उपयोगिता तथा वन संवर्धन, सोमांकन एवं प्रबंधन में इसके महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीजीपीएस आधारित सर्वेक्षण से वन क्षेत्रों में सटीक डेटा संग्रह संभव होता है जो दीर्घकालिक संरक्षण योजनाओं के लिए

अत्यंत उपयोगी है। इसी क्रम में उप-निदेशक, उदतीसोतानदी टाइगर रिजर्व वरुण जैन ने हज़ारों संकेतक मोबाइल एप्लिकेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह एक हार्थी मोनिटरिंग, मुवमेंट ट्रैकिंग, मानवझाड़ियों संबंध प्रबंधन तथा त्वरित सूचना साझा करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने बताया कि डीजीपीएस आधारित सर्वेक्षण से वन क्षेत्रों में सटीक डेटा संग्रह संभव होता है जो दीर्घकालिक संरक्षण योजनाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि

आधुनिक तकनीक, डिजिटल टूल्स एवं वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से वन एवं वन्यजीव संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है तथा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों को जमीनी स्तर पर बेहतर निष्पत्तियों में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने बताया कि डीजीपीएस आधारित सर्वेक्षण से वन क्षेत्रों में सटीक डेटा संग्रह संभव होता है जो दीर्घकालिक संरक्षण योजनाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि

4 फरवरी को होगी मंत्रिपरिषद की बैठक

नई दृष्टिबिंदु/ रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक 04 फरवरी 2026 को पुर्वान्ह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

इस, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकरमिक निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर मंत्रालय दुर्घटना में अजित पवार सहित अन्य लोगों के निधन को मुख्यमंत्री साय ने अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक

घटना बताया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अजित पवार का सम्पूर्ण जीवन कुषक कल्याण, जनसेवा और देश के विकास के लिए समर्पित रहा। उनका अस्मय निधन ने केवल उनके परिवार, समर्थकों और सहयोगियों के लिए, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति और सार्वजनिक जीवन के लिए भी अपूरणीय क्षति है।

मुख्यमंत्री साय ने दिवंगत आत्माओं को अर्द्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु श्रीराम से प्रार्थना की कि वे सभी को अपने शीर्षकों में स्थान दे तथा शोककुल परिजनों को इस अरहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की ओर से भी इस दुःखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की गई है।



बच्चे के गेमिंग एडिक्शन छुड़वाने के लिए अपनाएं यह ट्रिक्स

बच्चों को गेम खेलना काफी पसंद होता है। लेकिन यह देखने में आता है कि बच्चे आउटडोर गेम खेलने की जगह ऑनलाइन गेमिंग या फिर फोन में गेम इंस्टॉल करके गेम खेलने को अधिक प्राथमिकता देते हैं। हालांकि, इस तरह गेम खेलना उनके स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है। इससे ना केवल उनकी आंखों पर असर पड़ता है, बल्कि लगातार बैठे रहने से बच्चों को मोटापा व अन्य कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो जाती हैं। साथ ही साथ, अगर उन्हें गेमिंग एडिक्शन हो जाता है, तो इसे छुड़वाना काफी कठिन हो जाता है। हालांकि, ऐसे कई बच्चे हैं, जो लगातार फोन में गेम खेलते हुए इस हद तक एडिक्ट हो चुके हैं कि इसका असर उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर साफ़ तौर पर नजर आने लगा है। हो सकता है कि आपके बच्चे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो। तो ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज इस लेख में आपको कुछ ऐसे छोटे-छोटे तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप बच्चे के गेमिंग एडिक्शन को आसानी से दूर कर सकते हैं।

एकदम से ना छीनें गेम
अगर बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप उससे कभी भी छीनना न चाहें। इससे अगर बच्चे गुस्सेल हो जाते हैं और हो सकता है कि वह आपको बता न माने या फिर तोड़-फोड़ भी करे। इसलिए, आपको उनका ध्यान धीरे से भटकना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले एक-दो मिनट के लिए उसके गेम में इंटरैक्ट दिखाएं। उसके बाद आप धीरे से उसे किसी अन्य बातों में लगाएं और उसका ध्यान भटकाने का प्रयास करें।

बोरियत करें खतम
अमूमन यह देखने में आता है कि बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्ट इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय

होता है और उन्हें समझ ही नहीं आता कि वह अपने समय को किस तरह व्यय करें। इसके लिए, अगर उनकी दोस्ती अन्य बच्चों से करवाएं। साथ ही उन्हें कुछ ऐसे नए गेम लेकर दें, जिसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो सके। इतना ही नहीं, आप उन्हें बिजी रखने के लिए उन्हें किसी एक्टिविटी वर्कशॉप में जॉइन करवा सकते हैं। जब उनके पास पर्याप्त समय ही नहीं होगा, तो धीरे-धीरे उनका एडिक्शन कम होने लगेगा।

दें समय
किसी भी बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसके माता-पिता का समय। लेकिन आज के समय में अधिकतर पैरेंट्स बहुत अधिक बिजी रहते हैं और इसलिए, वह बच्चों के हाथों में फोन पकड़ देते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को फोन देने के स्थान पर उसे समय दें। जब आप अपना समय उन्हे देते हैं तो बच्चे गेम खेलने से ज्यादा आपके साथ समय बिताना व मस्ती करना पसंद करेंगे।

नकारात्मक पहलू समझाएं
अगर बच्चा उम्र में बड़ा है तो ऐसे में आप इस उपाय को भी अपना सकते हैं। आप उसे जबरदस्ती गेम छीनने या गुस्सा करने के स्थान पर लंबे समय तक गेम खेलने के नकारात्मक पहलुओं के बारे में बताएं। आज के समय में बच्चा कोई भी काम तभी करना पसंद करता है, जब उसे उसकी पूरी जानकारी हो। इसलिए आप उसके नेगेटिव इफेक्ट समझाएं। साथ ही, उसका स्क्रीन टाइम भी सेट करें।



ऑफिस में मिलेगी आपके काम को तबज्जो, अपनाएं यह ट्रिक्स

अगर ऑफिस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको ऑफिस में कोई भी नोटिस नहीं करता है तो आप इन आसान ट्रिक्स को अपनाने के बाद सबकी नजरों में आसानी से आ सकती हैं।

यह तो हम सभी जानते हैं कि सफलता की पहली सीढ़ी मेहनत ही है। सिर्फ मेहनत ही वह चाबी है, जिसके जरिए आप सफलता का ताला खोल सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप अपनी लाइफ में सबसे सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। ऑफिस में आप अपना सारा काम समय पर और बेहतर तरीके से पूरा करती हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी नोटिस न करता तो। यकीनन आपको बुरा ही नहीं लगेगा। आज के समय में अगर आपको सफल होना है तो यह जरूरी है कि आप हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी करें।

अगर आप सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती हैं और उसे कोई नोटिस ही नहीं करती तो आपके लिए सफलता प्राप्त करना बेहद कठिन हो जाएगा। इसलिए मेहनत करने के साथ-साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखनी है कि ऑफिस में आपके सहकर्मी खासतौर से आपके सीनियर्स व बॉस आपको गुणों व काम की अहमियत को पहचानें, क्योंकि जब उन्हें ऐसा महसूस होगा कि आप उनके ऑफिस के लिए बेहद जरूरी हैं, तभी वह आपको महत्व देंगे और आपके लिए सफल होने के रास्ते बनाएंगे। तो चलिए आज हम आपको ऐसी कुछ आसान ट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप ऑफिस में सबकी नजरों में आ सकती हैं और ऑफिस वर्कर्स आपके काम को तबज्जो देने लगेगे।



नए प्रोजेक्ट में हों शामिल

अक्सर देखने में आता है कि जिन रिक्लड लोगों को ऑफिस में नोटिस नहीं किया जाता, उसकी मुख्य वजह होती है कि उन्हें काम करने की सही स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता होता। मसलन, अगर कंपनी के पास कोई नया प्रोजेक्ट आया है तो आप आपको बढकर उसकी जिम्मेदारी मांगें। अमूमन ऐसे लोग पीछे रहते हैं और जब किसी दूसरे को प्रोजेक्ट लीडर बना दिया जाता है तो आप सिर्फ मेहनत ही करती रह जाती हैं और आपको मेहनत का सारा क्रेडिट प्रोजेक्ट लीडर को मिल जाता है।

बोलें बिजनेस मीटिंग्स में

जो महिलों ऑफिस में कड़ी मेहनत करती हैं, उन्हें कंपनी को बेहतर बनाने के कुछ युक्ति आइडियाज के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी वह बिजनेस मीटिंग्स में नहीं बोलती। कई बार वह सोचती हैं कि ना जाने उनका आइडिया दूसरों को कैसा लगे और कई बार वह घबराहत और डर के कारण चुप रहनी

पसंद करती हैं। जिसके कारण किसी का ध्यान उन पर नहीं जाता। इसलिए बिजनेस मीटिंग्स में बोलने की कोशिश करें। भले ही आपको आइडिया किसी को पसंद न आए लेकिन जब आप अपने निवार सभों के समक्ष पेश करती हैं तो इससे लोग आपको नोटिस करते हैं। साथ ही इससे उन्हें यह भी पता चलता है कि आप अपने ऑफिस रिसयान्सिबिलिटी से अलग भी कंपनी को बेहतर बनाने के बारे में सोचती हैं।

ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर

ऑफिस में अगर आपको अपनी अच्छी इमेज बनानी है तो कभी भी ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा न बनें। इससे कुछ समय के लिए आपको भले ही फायदा मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपकी इमेज को खराब करेगा और इससे आपके करियर को नुकसान ही पहुंचेगा। इसलिए कभी भी ऑफिस में किसी भी तरह का हिस्सा न बनें (कोशिश करें कि आपके रिश्ते ऑफिस में सभी से बेहतर हों।)

सोशल मीडिया का सहारा

यह भी ऑफिस में नोटिस किए जाने का एक अच्छा आइडिया है। आप अपने सोशल अकाउंट से अपने ऑफिस वर्क व अपनी कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स के बारे में लोगों को बताएं। साथ ही उनके लिंक्स ऑफिस में अपने सीनियर्स व अन्य सभी के साथ शेयर करें। ऐसा करने से आपके सीनियर्स आपको नोटिस करते हैं। साथ ही यह यह ऑफिस में बेटे के लिए कभी भी बेहतर की तरह आइडियाज के बारे में पता चलाएगा। इसका एक अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलता है।



नाश्ते में बनाएं पनीर रेसिपीज

पनीर एक ऐसी डिश है, जिसे चाहे किसी भी रूप में खाया जाए, यह उत्तनी ही डिलिशियस लगती है। आमतौर पर, यह देखने में आता है कि लोग पनीर को या तो सब्जी के रूप में खाना पसंद करते हैं या फिर उसे अपने इवनिंग स्नैक्स का हिस्सा बनाते हैं। जबकि यह एक बेहद ही वर्साटाइल फूड इंग्रिडिएंट है और इसलिए आपके पास इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के आइडियाज भी कम नहीं हैं। पनीर को प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है और हर मील में आपको प्रोटीन को जगह अवश्य देनी चाहिए। इसलिए, अगर आप अपने दिन को एक किकस्टार्ट देना चाहती हैं तो ऐसे में ब्रेकफास्ट में पनीर का सेवन करना अच्छा विचार हो सकता है। इतना ही नहीं, आप पनीर के परांठे से अलग भी कई रेसिपीज को अपने ब्रेकफास्ट का हिस्सा बना सकती हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको पनीर की कुछ ऐसी रेसिपीज के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें पनीर की मदद से तैयार किया जा सकता है-

पनीर चीज़ टोस्ट

पनीर और चीज़ की मदद से बनने वाले इस टोस्ट को आप हर दिन नाश्ते में बनाना और खाना पसंद करेंगे। इसे बनाना भी बेहद आसान है।



आवश्यक सामग्री

- 2 चम्मच मखन
- 1 छोटा चम्मच अरक लहसुन का पत्ता
- एक चौथाई कप बारीक कटा प्याज
- एक चौथाई कप बारीक कटी शिमला मिर्च
- स्वानुसार लाल मिर्च पाउडर
- एक चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला
- एक चौथाई छोटा चम्मच धनिया पाउडर
- 1 कप कढ़कूस किया हुआ पनीर
- ब्रेड स्लाइस
- अन्य सामग्री
- ब्रेड स्लाइस
- 1 कप कढ़कूस किया हुआ मोमोरोला चीज़ (सिंप्ली प्लेक्स
- रेमिस बर्हस

टोस्ट बनाने का तरीका

- सबसे पहले पनीर को कढ़कूस या क्रबल करके एक तरफ रख दें।
- अब एक पैन में 2 चम्मच मखन डालकर गरम करें।
- मखन के पिघलने पर इसमें 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और हल्का भूनें।
- अब इसमें प्याज और शिमला मिर्च डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
- अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर मिलाएं करते हुए चलाएं।
- अब इसमें कढ़कूस पनीर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और फिर आंच बंद कर दें।
- अंत में स्वानुसार नमक डालकर एक बार फिर से मिलाएं।
- अब बारी आती है सैंडविच बनाने की। इसके लिए 1 कप मोमोरोला चीज़ को कढ़कूस कर लें और एक तरफ रख दें।
- ब्रेड स्लाइस या तेल फ्री ब्रेड। इस दौरान आंच को लो रखें।
- फिर उन पर ब्रेड के टुकड़े रख दें। आप तवा या पैन के आकार के आधार पर एक बार में 2 से 3 ब्रेड स्लाइस रख सकते हैं।

पनीर पैटीज

पनीर पैटीज एक आसान और इटपट बनने वाला नाश्ता है जिसे आप पनीर की अलावा उबले हुए आलू, कॉर्नफ्लोर और कुछ मसालों के साथ आसानी से बना सकती हैं।

बनाने का तरीका

- सबसे पहले आलू को अच्छी तरह धोकर थोड़ा नमक और पानी के साथ उबालें।
- अब आलू को टंडा होने दें। फिर इन्हें छीलकर एक बाउल में आलू मिश्रण या फोर्क से मेश कर लें।
- अब पनीर को कढ़कूस कर लें और मसले हुए पनीर में मिला दें।
- साथ ही काली मिर्च पाउडर, कॉर्नफ्लोर और आवश्यकतानुसार नमक डालें।
- साथ ही काली मिर्च पाउडर, कॉर्नफ्लोर और आवश्यकतानुसार नमक डालें।
- तली हुई टिक्की को अच्छी तरह पनीर में डालें।
- एक तरफ से सुनहरा होने पर इन्हें पलट दें और दूसरी तरफ से भी सुनहरा और करारे होने तक तलें।
- तली हुई टिक्की को अच्छी तरह पनीर में रखें ताकि अतिरिक्त तेल सोख लें।
- पनीर पैटीज को टोमेटो केचप या पुदीने की चटनी या धनिया के साथ परोसें।

आवश्यक सामग्री

- 4 से 5 आलू उबले हुए
- पनीर
- आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
- 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर
- आवश्यकतानुसार नमक
- आवश्यकतानुसार तेल या घी



बैग्स हट महिला की एसेसरीज का एक हिस्सा है। आपको मार्केट में कई डिफरेंट स्टाइल के बैग्स मिल जाएंगे। इनमें छोटे पार्टीवियर बालच से लेकर ओवरसाइज्ड हैंगबैग जैसी एक वाइड रेंज मौजूद हैं। अमूमन देखने में आता है कि महिलाएं अलग-अलग ओकेज के अनुसार, डिफरेंट स्टाइल बैग खरीदती हैं।

यकीनन डिफरेंट लुक पाने का बैग्स एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एक सच यह भी है कि इस तरह आपके काफी सारे पैरे खर्च हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आपके पास बैग्स का एक बड़ा कलेक्शन हो जाता है। तो फिर आपको उनकी केयर करने व उन्हें रखने के लिए अच्छे खासे स्पेस की जरूरत होती है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती तो इसका दूसरा विकल्प है कि आप एक ही बैग को अलग-अलग अंदाज में कैरी करें और एक डिफरेंट लुक पाएं। ऐसा ही एक बैग है बेल्ट बैग। बेल्ट बैग स्टाइल करने के कई तरीके हैं। इस यह आपके उपर निर्भर करता है कि आप उसे किस ओकेजन के लिए कैरी करना चाहती हैं। तो चलिए जानते हैं कि

इस तरह कैरी करें बेल्ट बैग, दिखेंगी बेहद स्टाइलिश

बेल्ट बैग को अलग-अलग अंदाज में किस तरह कैरी किया जाए-
क्रॉस बॉडी स्टाइल
बेल्ट बैग को अगर एक डिफरेंट स्टाइल में कैरी करने की बात हो तो उसे क्रॉस बॉडी बैग की तरह कैरी करना यकीनन एक अच्छा आइडिया है। यह आपको एक फकी लुक देता है। क्रॉस बॉडी बैग की तरह बेल्ट बैग की पहनते समय आप इसे वन शोल्डर पर क्रॉस करते हुए पहना जाता है। अगर आप टी-शर्ट वियरें या फिर वेस्टर्न वियर पहन रही हैं तो ऐसे में बेल्ट बैग को क्रॉस बॉडी स्टाइल में कैरी कर सकती हैं।
शोल्डर बैग स्टाइल
बेल्ट बैग को कैरी करने का एक

सिंपल तरीका है, लेकिन यह आपको एक फेमिनिन लुक देता है। इस तरह से आप बेल्ट बैग को केजुअल से लेकर ऑफिस तक कैरी कर सकती हैं। इस स्टाइल में एक कंधे पर बैग को कैरी किया जाता है। यह कुछ ऐसे ही है, जैसे आप कॉलेज में अपने रेग्युलर बैग को वन शोल्डर पर कैरी करती थीं। अगर आप कॉलेज गोंइंग गालें हैं तो ऐसे में आप बेल्ट बैग को शोल्डर बैग स्टाइल में कैरी कर सकती हैं।
वलच स्टाइल
अगर आप कहीं बाहर पार्टी में जा रही हैं या फिर डेटाइम में डेट का मन बनाया है तो ऐसे में आप बेल्ट बैग को अपनी वेस्ट पर पहनने की जगह वलच स्टाइल में कैरी करें। इस तरह अगर आप बेल्ट



बैग कैरी कर रही हैं तो बैग में से बेल्ट को रिमूव करें और वलच स्टाइल में कैरी करें। इस तरह से आप बेल्ट बैग को केजुअल से लेकर ऑफिस तक कैरी कर सकती हैं। इस स्टाइल में एक कंधे पर बैग को कैरी किया जाता है। यह कुछ ऐसे ही है, जैसे आप कॉलेज में अपने रेग्युलर बैग को वन शोल्डर पर कैरी करती थीं। अगर आप कॉलेज गोंइंग गालें हैं तो ऐसे में आप बेल्ट बैग को शोल्डर बैग स्टाइल में कैरी कर सकती हैं।

सुबह रनिंग पर जा रही हैं या फिर एयरपोर्ट लुक में भी इस तरह से वेस्ट बैग को कैरी किया जा सकता है। बेल्ट बैग को वेस्ट बैग स्टाइल में कैरी करने हुए आप कुछ वैरिआयटीज कर सकती हैं। मसलन, आप बैग को फॉर्म में रखें और बेल्ट आपकी कमर में बँध कर आपगी। इसके अलावा, अगर आप चाहें तो इसे फॉर्म पर ना करके साइड में बैग को लाएं। इस तरह से वेस्ट बैग देखने में काफी चलासी लगता है।



डॉक्टर संजीव शुक्ला ने जारी किया आदेश, नशे पर फुल स्टॉप, रायपुर में कानून का राज



नाम में संजीव, फैसेले में साहस

प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को 'शुक्ला मॉडल' कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर दिलाई बर्दास्त नहीं की जाएगी। अब हर थाना क्षेत्र में विशेष निगरानी और नियमित जांच अभियान चलाए जाएंगे।

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राजधानी में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने नशे के खिलाफ

कमिश्नरेंट सिस्टम की पहली बड़ी जीत

पुलिस कमिश्नरेंट व्यवस्था लागू होने के बाद यह पहला बड़ा और ठोस फैसला माना जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि नई व्यवस्था केवल नाम की नहीं, बल्कि एक्शन की है।

उन्होंने साफ संदेश दे दिया है—अब रायपुर में नशा नहीं, कानून चलेगा। यह फैसला युवाओं के भविष्य की रक्षा और शहर को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

ड्रग नेटवर्क में मची खलबली

ड्रग नेटवर्क में मची खलबली आदेश जारी होते ही नशे के कारोबारियों में हड़कंध मच गया है। कई दुकानों से प्रतिबंधित सामान

हटाया गया है और अवैध सप्लाई चैन पर भी अरस पड़ा है। पुलिस अब न्यू सुचनाओं के आधार पर लगातार कार्रवाई कर रही है।

मिलने वाला वह सामान उन्हें अपराध और बर्बादी की राह पर धकेल रहा था। कमिश्नर डॉक्टर शुक्ला ने इसी खतरे को भांपते हुए बिना देर किए सख्त कार्रवाई का रास्ता चुना।

जनता से अपील

पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने नागरिकों से अपील की है कि नशे के खिलाफ इस अभियान में सहयोग करें और कहाँ भी अवैध विक्री की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि 'यह लड़ाई सिर्फ पुलिस की नहीं, पूरे समाज की है।'

स्वास्थ्य खबर

नकली दवा घोटाले में अधिकारी की मिलीभगत के खिलाफ ठरक का बड़ा एक्शन, EOW और स्वास्थ्य मंत्री से की कड़ी कार्रवाई की मांग



रायपुर। नकली दवाओं के गंभीर प्रकरण में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर संजय नेताम द्वारा आरोपी दवा व्यापारी से गुप्त बैठक किए जाने की खबर सामने आने के बाद ठरक ने इस पूरे मामले को लेकर आज सख्त रुख अपनाते हुए शासन-प्रशासन के समक्ष जोरदार तरीके से शिकायत दर्ज कराई।

शांतनू के प्रतिनिधिमंडल ने आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (EOW) के DIG गोवर्धन टाकुर से मुलाकात कर उन्हें पूरे घटनाक्रम से विस्तारपूर्वक अवगत कराया तथा भ्रष्टाचार, जांच में हस्तक्षेप, आरोपी से सटगोट और आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ जैसे गंभीर बिंदुओं को रखते हुए औपचारिक सी.पी. ज्ञान के माध्यम से यह मांग की गई कि असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर संजय नेताम की भूमिका को उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए, उनको चल-अचल संपत्तियों की जांच हो, मोबाइल नंबर जब्त कर डिजिटल फॉरेंसिक परीक्षण कराया जाए, बैंक खातों के लेन-देन की जांच की जाए तथा साक्ष्यों से डेडछाड़ रोकने के लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाया जाए। इस पर DIG गोवर्धन टाकुर ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

इसके पश्चात शांतनू ड्रा के सभी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री यशम विहारी जसवाल के निवास पहुंचे और वहां भी पूरे प्रकरण को लेकर शिकायत दर्ज कराई। संघटन ने स्पष्ट रूप से कहा कि नकली दवाओं जैसे संवेदनशील अपराध में यदि जिम्मेदार अधिकारी ही आरोपियों को संभाल देंगे तो यह सीधे आम नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, जिसे किसी भी हाल में बर्दास्त नहीं किया जाएगा। शांतनू ड्रा ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में दौरेपथ के फरिद और और कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो संजय जनिहरी में सड़क की लड़ाई लड़ने को बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज के इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शांतनू ड्रा के नेतृत्व में प्रेक्षा महाविद्यालय निबंधक बनेल, महामंत्री सुरज साहू, उपाध्यक्ष भोजराज, विमल साहू, अभिनव सोनकर, अथर्व, नवीन, अनिल सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

टेक्स नहीं भरने पर कटे गए नल कनेक्शन

दुर्ग। नगर पालिक निगम द्वारा बकाया कर वसूली को लेकर लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बॉर्ड नंबर 28 में सोहन सिंह/तुलसा सिंह द्वारा लंबे समय से 1,34,807 रुपये का टैक्स जमा नहीं किए जाने पर उनके घरिसर के दो नल कनेक्शन विच्छेदित किए गए। इसी बॉर्ड में पुष्पा देवी/जगत सुवर्चरी के यहां भी 53,349 रुपये बकाया टैक्स नहीं चुकाने पर एक नल कनेक्शन काटा गया। कार्रवाई के दबाव में बॉर्ड 28 के ही कृपाल सिंह ने मौके पर 14,872 रुपये टैक्स राशि जमा की। वहीं बॉर्ड नंबर 27 में सरस्वती शिराली ने नल कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई से बचने के लिए 23,497 रुपये का शुभान जमा किया। इसी बॉर्ड में संजय ताम्रकार ने भी 15,673 रुपये टैक्स राशि निगम में जमा की।

चतुर्थ दीक्षांत समारोह में 1536 छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर व पीएचडी दी गई उपाधि दीक्षांत समारोह केवल पढ़ाई पूरी करने का अवसर नहीं, जिम्मेदारियों भरी यात्रा की शुरुआत है - डेका



नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

शिदा किसी एक दिन समाप्त नहीं होती और सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है

राज्यपाल रमन डेका ने विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल पढ़ाई पूरी होने का अवसर नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक नई जिम्मेदारियों भरी यात्रा की शुरुआत है। राज्यापाल ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा किसी एक दिन समाप्त नहीं होती और सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमक देश है और यह क्षेत्र ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं और छोटे किसानों की आय का मुख्य स्रोत है। राज्यापाल ने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अव्यवस्था में पशुपालन और मत्स्य पालन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आज पशुधन क्षेत्र को केवल सखा बढाने के बजाय आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रवृत्तियों से मजबूत करने की आवश्यकता है।

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की भूमिका महत्वपूर्ण - रामविचार नेताम

प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अपने उद्घोषण में कहा कि छत्तीसगढ़ की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की भूमिका महत्वपूर्ण है। दीक्षांत केवल डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं है, यह उस नई यात्रा का आरंभ है। जहाँ ज्ञान, प्रयोग, सवाचार और समाज सेवा एक साथ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि उपाधि प्राप्त करने के बाद आप सभी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नये दूत, नये पद प्रदर्शक और नये परिवर्तनकर्ता हैं। आपके कोशल, आपके अनुभव और आपके प्रतिबद्धता से किसानों, पशुपालकों और मछुवारी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़े स्टार्टअप को प्रोत्साहन, अनुदान और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। जब आप किसी पशु का उपचार करते हैं, किसी किसान को मार्गदर्शन देते हैं, यह किसी मछुवारी को नई तकनीकी सिखाते हैं, तब आप पेशेवर नहीं रहते हैं, आप परिवर्तन के वाहक बन जाते हैं। कृषि मंत्री ने दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

दुर्ग, दाय बसुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के चतुर्थ दीक्षांत समारोह आज विश्वविद्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका की गरिमामयी मौजूदगी में संपन्न हुई।

ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चन्द्राकर और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, अहिंवार विधायक डोमन लाल कोसेबाबा भी मौजूद थे।

राज्यापाल श्री डेका ने विश्वविद्यालय द्वारा संक्रामक रोगों की रोकथाम और नस्ल सुधार के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने डेयरी प्रौद्योगिकी के छात्रों को मिलावट की समस्या के प्रति सचेत करते हुए गुणवत्ता पर ध्यान देने का, ताकि भारतीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर परीसर्व बन सकें। राज्यापाल ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में उन्होंने कोंकर जिले की सफलता से प्रेरणा लेने और आधुनिक तरीकों को अपनाने की बातें कही।

राज्यापाल श्री डेका ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे केवल नैतिकी दृढ़ता केवल न बनें, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ रोजगार देने वाले बनें। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा और डेयरी जैसे विषय केवल पढ़ाई नहीं बल्कि मानवता की सेवा के माध्यम हैं। राज्यापाल ने शिक्षकों और अभिभावकों के योगदान की सराहना करते हुए युवाओं को आत्मविश्वास के साथ देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर.आर.बी. सिंह ने विश्वविद्यालय के प्रति प्रतिबद्ध

प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. मोशे सो शाह जैसे विषय केवल पढ़ाई नहीं बल्कि मानवता की सेवा के माध्यम हैं। राज्यापाल ने शिक्षकों और अभिभावकों के योगदान की सराहना करते हुए युवाओं को आत्मविश्वास के साथ देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर.आर.बी. सिंह ने विश्वविद्यालय के प्रति प्रतिबद्धता के साथ देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

कवर्धा डॉ. एम.के. गेंदले, अंधिछत्ता दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर डॉ. सुधीर उपरीत, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. मिश्र चंदेल, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सहित आर सक्सेना विश्वविद्यालय के उपाधिधारी विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे।

बापू इन्हें माफ करना....

भिलाई। 30 जनवरी के दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। पूरा देश रोया था और गांधी जी की कमी देश के आम लोग आज भी महसूस करते हैं। राजनीतिक रीढ़ी पत्रकार नरान निगम भिलाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तो स्थापित कर दी गई लेकिन आज बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने कोई नहीं पहुँचा। गांधी जी के प्रतिमा पर 26 जनवरी को माला बंधाई गई थी वह माल भी प्रतिमा के गिरा मरुदाई हुई है। प्रतिमा के आसपास लग्गी टाइटिस के रंग उड़ रहे हैं। प्रतिमा की साफ-सफाई भी नहीं हो रही है यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं की बापू इन्हें माफ करना ये लोग नादान हैं।



विभागीय परीक्षा का आयोजन, संभागायुक्त राठौर ने किया परीक्षा केंद्र का निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ शासन गृह-सि विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) के अंतर्गत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन 27 जनवरी से 03 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। इस परीक्षा के सुचारु संचालन हेतु भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी), दुर्ग को परीक्षा केंद्र के रूप में नामांकित किया गया है।



अपराध 1.60 लाख के बदले 22 लाख की अवैध वसूली का दबाव

पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सूदखोर आरोपी गिरफ्तार, 11 चैकबुक व इकरानामा जब्त

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग जिले में सूदखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पदमनाभपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध ब्याज वसूली और धमकी देकर रकम पेंडेंते वाले आरोपी हरीश पारख को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, पीड़ित ने 27 जनवरी को थाना पदमनाभपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसने आरोपी से 1.60 लाख उधार लिए थे। आरोपी द्वारा 10 प्रतिशत ब्याज वसूला जाता था और समय पर भुगतान न होने पर रकम दोगुनी करने की धमकी दी जाती थी।

पीड़ित अब तक 3.20 लाख मूलधन और ब्याज के रूप में चुका चुका था, इसके बावजूद आरोपी ने दबाव बनाकर बक के 11 खाली



लिखा। मामले में अपराध क्रमांक 89/2026 धारा 296, 351(2), 308(2) बीएनएस एवं कर्जा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अवैध वसूली और चैक लेने की बात स्वीकार की। इसके बाद 29 जनवरी को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

जप्त सामग्री में 11 हस्ताक्षरित चेक, इकरानामा, साहकारी लाइसेंस शामिल हैं। आरोपी में हरीश पारख (60 वर्ष), निवासी न्यू बोर्सी, दुर्ग है।

पुलिस का संदेश

दुर्ग पुलिस ने आरोपी को से अपील की है कि सुरखोरी, धमकी वा अवैध वसूली से जुड़े मामलों में बिना डर के शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे आरोपी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Rudra Engineers

CIVIL CONTRACTOR AND BUILDING MATERIAL SUPPLIER

बनाइए अपने सपनों का आशियाना, रफ़ा इंजीनियर्स के संग

कुशल इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट की निगरानी में घर निर्माण मटेरियल सहित

रिवरिफ एफ़ माड	सम्पूर्ण निगमाण माड	सम्पूर्ण निगमाण माड एवं मटेरियल सहित
₹849 प्रति वर्ग फुट	₹1299 प्रति वर्ग फुट	₹1375 प्रति वर्ग फुट

Complete Solution For All Your Civil Needs

- मटेरियल कंसल्टेशन के साथ
- इंटीरियर और एक्सिटेरियर के लिए 3 डी डिजाइनिंग
- मैस्यूरिगेशन और कम्प्लियन्स रैपट की प्लानिंग
- पूर् कंसल्टेंट वॉल ग्राउन्डेंट

FREE फ्री कॉन्सल्टिंग, फ्री डिजाइन, फ्री एक्सीटेरियर डिजाइन, फ्री एंड वॉल प्लानिंग

📍 शास्त्री नगर, शास्त्री चौक, वार्ड - 27, भिलाई

9893541782
9993262337